सबकान्ट्रेक्टर व कंसलटेंट को सेवाकर में राहत

भोपाल | देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों सबकान्ट्रेक्टर्स एवं कंसलटेंट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने इस वर्ष दिवाली का तोहफा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सबकान्ट्रेक्टर्स एवं कंसलटेंट की सेवाएं कर मुक्त कर दी हैं। इसके अंतर्गत अब तक केवल ठेकेदार ही सेवाकर मुक्त थे, सब कान्ट्रेक्चर कंसलटेंट, मेन्टनेंस, आरएंडडी एवं अन्य तमाम एजेंसियों पर सेवाकर का दायित्व आता था। इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसलटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया संगठन के अध्यक्ष एलएन मालवीय और एडवोकेट संजय व्यास ने देशभर के लगभग 1500 से अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदारों का प्रतिनिधित्व करते हुए सीबीईसी में अपना प्रजेंटेशन 8 अगस्त को दिया था। इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी एजेंसियों में हो रही परेशानी को समझते हुए सीबीईसी ने सर्कुलर क्रमांक 1381, 21 अक्टूबर को जारी किया है। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सबकान्ट्रेक्टर्स और कंसलटेंट्स सेवाओं को सेवाकर से मुक्त कर दिया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसियां सेवाकर से मुक्त

पीपुल्स संवाददाता, भोपाल

देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों सबकान्ट्रक्स-कंसलटेंटस को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने इस वर्ष दिवाली तोहफा दिया है। जिसके अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंसलटेंटस की सेवाएं कर मुक्त कर दी गई है। प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसलटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया संगठन के अध्यक्ष एलएन मालवीय और एडवोकेट

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राजक्ट स जुड़ ठकदारा का प्रतिनिधित्व करते हुए सीबीईसी में अपना प्रजेंटेशन 8 अगस्त 2011 को दिया था।

सीबीईसी ने 21अक्टूबर 11 को एक सर्कुलर जारी किया , इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सबकान्ट्रक्स व कंसलटेंटस एवं एजेंसियों की सेवाओं को सेवाकर से मुक्त कर दिया है।

सब कांट्रेक्टर व कंसल्टेंट को सेवाकर में राहत

भोपाल (कार्पोरेट प्रतिनिधि)। देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों सब कांटेक्टर्स व कंसल्टेंट्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ [illegible] ने दिवाली का तोहफा दिया [illegible] इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सब कांट्रेक्टर्स, कंसल्टेंट्स की सेवाएं कर से मुक्त कर दी गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक केवल ठेकेदार ही सेवाकर से मुक्त थे और सब कांट्रेक्टर्स, मेंटेनेंस, आरएंडडी एवं अन्य तमाम एजेंसियों पर सेवाकर का दायित्व आता था। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट्स एसो. ऑफ इंडिया संगठन के अध्यक्ष एलएन मालवीय ने इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। मालवीय ने बताया [illegible] जाता था। श्री मालवीय ने बताया कि संगठन के अध्यक्ष के नाते उन्होंने और एडवोकेट संजय व्यास (इंदौर) ने सीबीईसी में अपना प्रजेंटेशन 8 अगस्त 2011 को दिया था। श्री मालवीय ने [illegible] वाले लगभग 500 करोड़ रुपए का भार समाप्त हो गया है।